भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-144**

उत्तर देने की तारीख-20/07/2026

**बिहार में नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना**

†144. **डॉ. आलोक कुमार सुमन:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में स्थापित या उन्नत किए गए केंद्रीय शिक्षण संस्थानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का बिहार में कोई नया केंद्रीय विश्वविद्यालय, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) या अन्य उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार को समग्र शिक्षा के अंतर्गत जारी की गई निधि कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा डिजिटल शिक्षा और अनुसंधान अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा स्नातकों की रोजगार क्षमता को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सुकान्त मजूमदार)**

(क) और (ख): वर्ष 2014 से पहले, देश में 16 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कार्यात्मक थे। वर्ष 2014 के बाद, बजट घोषणा वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 के अनुसरण में, छह नए आईआईटी आंध्र प्रदेश (आईआईटी तिरुपति), केरल (आईआईटी पलक्कड़), छत्तीसगढ़ (आईआईटी भिलाई), जम्मू और कश्मीर (आईआईटी जम्मू), गोवा (आईआईटी गोवा) और कर्नाटक (आईआईटी धारवाड़) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, बजट घोषणा वर्ष 2015-16 के अनुसरण में, झारखंड में भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद को वर्ष 2016 में आईआईटी का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में देश में 23 आईआईटी कार्यात्मक हैं।

वर्ष 2014 से पहले देश में 13 भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) कार्यात्मक थे और वर्तमान में 22 आईआईएम हैं। वर्ष 2014 के बाद, आठ नए आईआईएम पंजाब (आईआईएम अमृतसर), बिहार (आईआईएम बोधगया), ओडिशा (आईआईएम संबलपुर), जम्मू और कश्मीर (आईआईएम जम्मू), हिमाचल प्रदेश (आईआईएम सिरमौर), महाराष्ट्र (आईआईएम नागपुर), आंध्र प्रदेश (आईआईएम विशाखापत्तनम) और असम (आईआईएम गुवाहाटी) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2023 में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग (एनआईटीआईई), मुंबई को आईआईएम मुंबई में परिवर्तित कर दिया गया है।

वर्ष 2014 से पहले देश में 30 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और एक भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी) कार्यात्मक थे और वर्तमान में एक आईआईईएसटी के अलावा 31 एनआईटी हैं। एनआईटी आंध्र प्रदेश की स्थापना वर्ष 2015 में की गई है।

वर्ष 2014 से पहले देश में 9 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) कार्यात्मक थे और वर्तमान में 25 आईआईआईटी हैं। वर्ष 2014 के बाद, सोलह नए आईआईआईटी आंध्र प्रदेश (आईआईआईटीडीएम कुरनूल), हरियाणा (आईआईआईटी सोनीपत), हिमाचल प्रदेश (आईआईआईटी ऊना), पश्चिम बंगाल (आईआईआईटी कल्याणी), कर्नाटक (आईआईआईटी धारवाड़, आईआईआईटी रायचूर), मणिपुर (आईआईआईटी सेनापति), केरल (आईआईआईटी कोट्टायम), उत्तर प्रदेश (आईआईआईटी लखनऊ), झारखंड (आईआईआईटी रांची), महाराष्ट्र (आईआईआईटी पुणे, आईआईआईटी नागपुर), मध्य प्रदेश (आईआईआईटी भोपाल), गुजरात (आईआईआईटी सूरत), बिहार (आईआईआईटी भागलपुर) और त्रिपुरा (आईआईआईटी अगरतला) राज्यों में स्थापित किए गए हैं।

वर्ष 2014 से पहले देश में 5 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) और एक भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) कार्यात्मक थे। वर्तमान में 7 आईआईएसईआर हैं जिनमें से दो नए आईआईएसईआर आंध्र प्रदेश (आईआईएसईआर तिरुपति) और ओडिशा (आईआईएसईआर बेरहामपुर) राज्य में वर्ष 2014 के बाद स्थापित किए गए।

वर्ष 2014 से पहले देश में 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) कार्यात्मक थे और वर्तमान में 48 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। आठ सीयू बिहार (महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, बिहार), आंध्र प्रदेश (आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश), तेलंगाना (सम्माक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय तेलंगाना), दिल्ली (केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली), लद्दाख (सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय लद्दाख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में इस मंत्रालय में बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक स्थल के निकट एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एक सतत् और निरंतर प्रक्रिया है। आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर शैक्षिक संस्थान खोले जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्ण पहुंच, समानता और समावेशन सुनिश्चित करने का प्रावधान करती है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई करना केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है। सरकार सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ग): वित्त वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा योजना के तहत बिहार के लिए 5518.47 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(घ): शिक्षा मंत्रालय देश भर के स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए समग्र शिक्षा के तहत आईसीटी और डिजिटल पहल कार्यान्वित करता है। इन पहलों का उद्देश्य शिक्षण और

अधिगम  की प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। यह अन्य बातों के साथ-साथ कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए कौशल एक्सपोजर और कक्षा 9 से 12 के लिए एनएसक्यूएफ-संरेखित कौशल पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करके व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देता है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में 17 मई, 2020 को पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई थी, जो देश भर में शिक्षा तक बहु-पद्धति पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन पहलों की प्रभावशीलता का उपयोग करने, निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एनसीईआरटी के साथ सहयोग करते हैं। एनसीईआरटी इन पहलों की गुणवत्ता के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित मार्गदर्शन/फीडबैक भी प्रदान करता है।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-विषय वस्तु और सभी कक्षाओं (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए क्यूआर कोड वाली एनर्जाइज्ड टेक्स्टबुक्स (ईटीबी) प्रदान करने के लिए राष्ट्र की डिजिटल अवसंरचना है। महत्वपूर्ण आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देने और रचनात्मकता को स्थान देने के लिए, 614 से अधिक वर्चुअल प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई हैं।

शिक्षा मंत्रालय एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमईआईसीटी) भी कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा की सभी प्रक्रियाओं में आईसीटी की क्षमता का लाभ उठाना है। एनएमईआईसीटी योजना के तहत स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयम) प्लेटफॉर्म प्रमुख संस्थानों द्वारा तैयार की गई सामग्री को प्रस्तुत करता है और यह "कोई भी, कहीं भी, कभी भी" के अधिगम दृष्टिकोण के साथ नि:शुल्क उपलब्ध है। अब तक, स्वयम के माध्यम से 4400 से अधिक अद्वितीय पाठ्यक्रमों की पेशकश की गई है। इन पाठ्यक्रमों में 6 करोड़ से अधिक के संचयी नामांकन हुए हैं।

अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन (एएनआरएफ) की स्थापना की है जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की अनुसंधान क्षमता का उपयोग करना, शैक्षणिक अनुसंधान में सहयोग प्रदान करना तथा उभरती प्रौद्योगिकियों और राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त अनुसंधान को सुगम बनाना है। अन्य पहलों, जैसे प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप (पीएमआरएफ), शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (स्पार्क), इम्प्रिंट, उच्चतर आविष्कार योजना (यूएवाई) तथा उत्कृष्ट संस्थान (आईओई) के माध्यम से अनुसंधान क्षमता, नवाचार तथा शिक्षाविदों, उद्योगों एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बीच सहयोग को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है।

(ङ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में नियोजनीयता, उद्यमिता और आजीवन अधिगम के संवर्धन के लिए मुख्यधारा की उच्चतर शिक्षा के साथ कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के

एकीकरण की परिकल्पना की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामान्य, व्यावसायिक और अनुभवात्मक शिक्षा के एकीकरण को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के साथ अनुकूलित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ) को अधिसूचित किया है। राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क अकादमिक, व्यावसायिक और कौशल शिक्षा में ऋण संचय और हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है जबकि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) निर्बाध शैक्षणिक गतिशीलता में सहायता करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री कार्यक्रम (आईईडीपी) के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं जिससे स्नातक छात्रों को उनके डिग्री कार्यक्रमों के साथ एकीकृत संरचित इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के माध्यम से उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कौशल विकास को तकनीकी शिक्षा में शामिल करके सक्रिय रूप से सुदृढ़ कर रहा है। यह उद्योगों और संस्थानों के साथ साझेदारी करता है ताकि नियमित पाठ्यक्रम के साथ ऑनलाइन कौशल पाठ्यक्रमों की प्रस्तुत किया जा सके जिसमें साथ ही कौशल-केंद्रित कार्यक्रम, अनिवार्य इंटर्नशिप और बैचलर ऑफ वोकेशन (बी.वोक) जैसी व्यावसायिक डिग्री भी शामिल है। इन पहलों को छात्रों की व्यावहारिक क्षमताओं का निर्माण करने और रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, एआईसीटीई ने उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों के लिए व्यावहारिक प्रदर्शन सहित इंटर्नशिप, कौशल-निर्माण और संकाय संवर्धन में सहायता करने के लिए प्रमुख उद्योगों और संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

पाठ्यक्रम में रोजगार कौशल मॉड्यूल को नौकरी की भूमिकाओं/स्वयम पाठ्यक्रमों के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है जिसमें संचार कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमिता कौशल और हरित कौशल शामिल हैं।

कौशल विकास में सहायता करने के लिए स्वयम प्लस पोर्टल भी शुरू किया गया है जो कार्यबल के कौशल को बढ़ाने और फिर से कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्तमान में 17 क्षेत्रों में 89 उद्योग भागीदारों से 500 से अधिक पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं और एआई, डेटा विश्लेषक आदि जैसे उभरते क्षेत्रों पर प्रस्तुत किए गए हैं। अब तक, 6,00,000 से अधिक छात्रों ने प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया है।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को संरचित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करके अकादमिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच के अंतर को कम करती है। यह योजना अप्रेंटिसशिप एंबेडेड डिग्री कार्यक्रम (एईडीपी) के माध्यम से उद्योग-एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता(एआई) जैसे उभरते क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप में सहायता करती है, और एनएटीएस मूल्यांकन और क्रेडिटाइजेशन फ्रेमवर्क के माध्यम से अकादमिक क्रेडिट एकीकरण की सुविधा प्रदान करती है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान, इस योजना के तहत 12.94 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया गया है। दिनांक 30.07.2024 को शुरू किए गए एनएटीएस 2.0 पोर्टल ने 11,355 से अधिक उच्चतर शिक्षा संस्थानों और 15,840 से अधिक प्रतिष्ठानों की भागीदारी को सक्षम बनाकर अप्रेंटिसशिप पारिस्थितिकी को और मजबूत किया है।

*****